

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
18.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 3796 का उत्तर

कर्नाटक में बिरूर से शिवमोगा रेलवे स्टेशन तक दोहरीकरण के कार्य में विलंब

3796. श्री बी. वाई. राघवेन्द्र:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) कर्नाटक में बिरूर से शिवमोगा रेलवे स्टेशन तक दोहरीकरण के कार्य में विलंब के क्या कारण हैं;
- (ख) उक्त रेल लाइन के दोहरीकरण के कार्य के लिए अनुमानित समय-सीमा और बजटीय आवश्यकताएं क्या हैं; और
- (ग) इस क्षेत्र में संपर्क बढ़ाने और आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए उक्त परियोजना को प्राथमिकता देने हेतु नियोजित उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): रेलवे परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन क्षेत्रीय रेलवे-वार किया जाता है, न कि राज्य-वार, क्योंकि रेल परियोजनाएँ राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदाता, यातायात अनुमानों, अंतिम छोर संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्ग, संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्धन, राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई माँगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकता, व्यापार और पर्यटन सहित सामाजिक-आर्थिक विचारों आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है, जो चालू परियोजनाओं के थ्रोफॉर्वर्ड और निधि की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

कर्नाटक राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के दक्षिण पश्चिम रेलवे (एसडब्ल्यूआर), मध्य रेलवे (सीआर), दक्षिण रेलवे (एसआर) और दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर) जोनों के अंतर्गत आती हैं। लागत, व्यय और परिव्यय सहित रेल परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेलवे-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराया गया है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 47,016 करोड़ रूपए की लागत से 3840 कुल किलोमीटर लंबाई की 31 रेल परियोजनाएं (21 नई लाइनें और 10 दोहरीकरण) योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 1302 किलोमीटर लंबाई कमीशन की जा चुकी है और मार्च, 2024 तक 17,383 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है। सारांश निम्नानुसार है:

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (कि.मी. में)	कमीशन की गई लंबाई (कि.मी. में)	मार्च 2024 तक व्यय (करोड़ रूपए में)
नई लाइन	21	2556	395	7592
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	10	1284	907	9791
कुल	31	3840	1302	17383

कर्नाटक राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-2014	₹835 करोड़/वर्ष
2024-2025	₹7,559 करोड़ (9 गुना से अधिक)

बीरूर-शिवमोगा (63 किलोमीटर) के बीच दोहरीकरण के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण मई, 2016 में पूरा हो गया था, लेकिन कम यातायात अनुमानों के कारण परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। बहरहाल, नवीनतम लागत और यातायात अनुमानों का आकलन करने के लिए जून, 2024 में नया अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण स्वीकृत किया गया है।

किसी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन मंजूरी, लागत भागीदारी वाली परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा लागत का हिस्सा जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, बाधक जनोपयोगी सुविधाओं का

स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक मंजूरी, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण किसी विशेष परियोजना स्थल के लिए एक वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।
